कानपुर, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026
वर्षः 03, अंकः 31, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड रायबरेली में गांधी परिवार पर याचिका ...>Pg12

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफ़ान सोलंकी को झटका...>Pg03

मूल्यः 2 ₹

सड़क, रेल और हवाई यातायात पर ब्रेक, ठंड से बढ़ी परेशानी

यूपी को कोहरे ने जकड़ा

10 मीटर तक सिमटी विजिबिलिटी

30 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का कहर, जनजीवन बेहाल

3-5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, बारिश के भी आसार

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को घने कोहरे, शीतलहर और बर्फीली हवाओं ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों के 30 से अधिक जिले सुबह से ही कोहरे की चपेट में रहे। लखनऊ, आगरा, झांसी, अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, बरेली और मुरादाबाद सहित कई शहरों में हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए।

अलीगढ़ और झांसी जैसे जिलों में दृश्यता घटकर महज 10 मीटर तक सिमट गई। घने कोहरे के कारण हाईवे और संपर्क मार्गों पर सन्नाटा पसरा रहा। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज पछुआ हवाओं के साथ गलन ने ठंड को और तीखा बना दिया। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश जैसा अहसास करा रही थीं। लोग भारी ऊनी कपड़ों में लिपटे नजर आए, जबकि ग्रामीण और शहरी इलाकों में जगह-जगह अलाव जलते दिखे। प्रदेश के 30+ जिले घने कोहरे की गिरफ्त में हैं। अलीगढ़, झांसी में 10 मीटर तक विजिबिलिटी रह गई है। बुलंदशहर रहा सबसे ठंडा जिला रिकार्ड किया गया। जहां न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पूरे प्रदेश में सुबह-शाम गलन से ठिठुरन बढ़ गई है।

यातायात पूरी तरह प्रभावित

घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ा। हाईवे और प्रमुख सड़कों पर वाहन चालकों ने धीमी रफ्तार से सफर किया कई स्थानों पर सुबह के समय सड़कें लगभग खाली रहीं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 20 से अधिक ट्रेनें घंटों देरी से चलीं। मौसम के इस रुख से कई उड़ानें लेट होने से एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। वहीं ठंड के कारण रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या भी घट गई है। रात को बसों में नाममात्र के यात्री दिखे। इसके अलावा दिहाड़ी मजदूरों और खुले में काम करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह-शाम बाजारों में रौनक कम रही, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा लेते दिखे।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में ठंड का दौर अभी थमने वाला नहीं है। 1 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया अगले 24 से 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव है। 1 से 3 फरवरी के बीच पश्चिमी और पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। तराई और पूर्वी जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा बना रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह-शाम अनावश्यक बाहर निकलने से बचने और वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

खबर एक नजर में

- प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप
- अलीगढ़ और झांसी में दृश्यता घटकर सिर्फ 10 मीटर तक सिमटी
- बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला, न्यूनतम तापमान 8.6एष्ट
- तेज पछुआ हवाओं से सुबह-शाम गलन और ठिठुरन बढ़ी
- ओस की बूंदों से हल्की बारिश जैसा अहसास, नमी बढ़ी
- सड़क यातायात पर सबसे ज्यादा असर, हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए
- लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत कई स्टेशनों पर 20+ ट्रेनें देरी से
- कोहरे के कारण कई उड़ानें लेट, एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान
- ठंड के चलते रोडवेज बसों में सवारियों की संख्या घटी
- खुले में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा दिक्कत
- शहरों और गांवों में अलाव ही बने ठंड से बचाव का सहारा
- एक फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय
- 1-3 फरवरी के बीच बारिश की संभावना, ठंड और बढ़ने के आसार
- अगले 24-48 घंटों में तापमान में 3-5 डिग्री गिरावट संभव
- तराई और पूर्वी यूपी में हल्का से मध्यम कोहरा बना रहेगा

आंगन में खेल रही चार साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बहराइच। ग्राम पंचायत रमपुरवा गांव में गुरुवार देर शाम तेंदुए के हमले से चार वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई । घर के आंगन में खेल रही मासूम को तेंदुआ मुंह में दबोचकर उठा ले गया और कुछ ही दूरी पर हमला कर उसकी जान ले ली। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

निशानगाड़ा रेंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत रमपुरवा स्थित मुखिया फार्म निवासी चार वर्षीय अनुष्का गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे अपने घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान पास के गन्ने के खेत से निकला तेंदुआ अचानक घर में घुस आया और बच्ची को दबोचकर बाहर की ओर ले गया।

बच्ची की चीख-पुकार सुनकर परिजन शोर मचाते हुए पीछे दौड़े, लेकिन तब तक

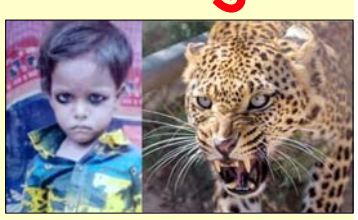

तेंदुआ घर से लगभग 50 मीटर दूर झाड़ियों के पास बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजन तत्काल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और तेंदुए की तलाश के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

निकाह का गवाह शारिक खान पीलीभीत से गिरफ्तार

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- केजीएमयू दुष्कर्म-धर्मांतरण केस में बड़ी गिरफ्तारी
- काजी की तलाश में लगातार दबिश, आरोपी को लखनऊ लाकर होगी पूछताछ

लखनऊ। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव के मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है। चौक कोतवाली पुलिस ने इस प्रकरण में नामजद आरोपी और निकाह के गवाह रहे शारिक खान को पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम आरोपी को पीलीभीत से लखनऊ लेकर रवाना हो गई है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, शारिक खान मुख्य आरोपी डॉ. रमीज मलिक के पिता सलीमुद्दीन के दोस्त का रिश्तेदार है। वह रमीज मलिक की पहली पत्नी के धर्मांतरण के बाद हुए निकाह में गवाह था। इसी आधार पर उसकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उसे आरोपी बनाया गया। पुलिस मामले में निकाह पढ़ाने वाले काजी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जांच में सामने आया है कि पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला फीलखाना निवासी काजी ने यह निकाह पढ़ाया था। काजी से पूछताछ को केस के लिए अहम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में केजीएमयू की एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने चौक कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया, गर्भपात कराया गया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। इस तहरीर पर 23 दिसंबर को रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीज मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि डॉ. रमीज मलिक इससे पहले आगरा की एक महिला डॉक्टर का धर्मांतरण कराकर निकाह कर चुका है। उसी निकाह में शारिक खान गवाह बना था। पीड़िता की तहरीर के आधार पर काजी जाहिद हसन राणा और शारिक खान को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 5 जनवरी को सलीमुद्दीन और खतीजा को गिरफ्तार किया गया। 9 जनवरी को 50 हजार का इनामी और फरार डॉ. रमीज मलिक गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब शारिक खान को पीलीभीत से गिरफ्तार कर लखनऊ लाने की तैयारी हो रही है। जहां उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

ब्लेडबाज आशिक को जेल

बोला- गला काटने का था इरादा

चेहरे-हाथों में आए 32 टांके, पुलिस को मिली धमकी वाली चैट

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नजीराबाद में शादी से मना करने पर युवक ने युवती पर सर्जिकल ब्लेड से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। बचाव के दौरान युवती के चेहरे और हाथों में 32 टांके आए हैं। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से धमकी भरी चैट बरामद की है और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में भदौरिया चौराहे पर बुधवार की शाम युवती पर सर्जिकल ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। आरोपी ने बताया कि बुधवार को उसने बताया था कि सात फरवरी को हरदोई में शादी है।

अब उससे बात न किया करे। इससे आक्रोशित होकर उसका गला काटने के इरादे से सर्जिकल ब्लेड से वार किया था। युवती के चेहरे व हाथों में करीब 32 टांके लगे हैं।

पीड़ित युवती दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि परिवार में माता-पिता, दो भाई और एक छोटी बहन है। पिता व भाई ठेला लगाते हैं।

जान से मारने की दे रहा था धमकी

वह और मां घरों में काम करती है। भदौरिया चौराहे के पास एक एल्युमीनियम दुकान में काम करने वाला काकादेव लोहारनभट्ठा निवासी गोलू जबरन दोस्ती का दबाव बनाकर परेशान कर रहा था।

उन्होंने सात फरवरी को शादी होने का हवाला देकर बातचीत करने से मना किया, तो वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल और मैसेज कर जान से मारने की धमकी दे रहा था।

गाल और दोनों हाथ बुरी तरह से कट गए

बुधवार रात को वह काम करके घर लौट रही थी तभी भदौरिया चौराहा के पास उसने रोक लिया। वह उससे रेस्टोरेंट चलने की बात कहने लगा। विरोध किया, तो गले पर सर्जिकल ब्लेड से वार करने की कोशिश की। गाल और दोनों हाथ बुरी तरह से कट गए।

आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा

लोगों ने भाग रहे गोलू को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। युवती की मां और छोटी बहन ने बताया कि आरोपी उनके मोबाइल पर लगातार गालीगलौज भेज रहा था जिसकी चैट पुलिस को सौंप दी है। नजीराबाद इंस्पेक्टर राजकेसर ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

कानपुर सेंट्रल सिटी साइड पर शुरू हुआ अस्थायी टॉयलेट का निर्माण

स्वराज्य इंडिया की खबर के बाद प्रशासन ने यात्रियों की असुविधा दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की

सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड पर एक भी वाशरूम न होने से महिलाएं परेशान

» यात्रियों ने तत्काल अस्थायी शौचालय बनवाने की माग उठाई

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड (प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर) स्टेशन परिसर में चल रहे नवनिर्माण और विकास कार्यों के बीच बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी सामने आ रही है। हालात इतने खराब है कि यहां एक भी सार्वजनिक वाशरूम नहीं है। नतीजतन स्टेशन के बाहर लगी टीन शेड की बैरिकेडिंग के किनारे पुरुष खुले में पेशाब करते दिखाई देते है, जिससे आसपास अस्वच्छता और बदबू फैल गई है। राहगीरों का गुजरना मुश्किल हो गया है और यात्री नाक पर हाथ रखकर निकलने को मजबूर हैं सबसे बुरी स्थिति महिलाओं की है। स्टेशन के इस हिस्से में शौचालय की सुविधा न होने के कारण उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है।

कई महिलाएं मजबूरी में सिर झुकाकर रास्ता पार करती दिखती है ताकि खुले में पेशाब करते लोगों को देखकर शर्मिंदगी न झेलनी पड़े यात्री धर्मेंद्र का कहना है कि निर्माण कार्य सालों से चल रहा है लेकिन अस्थायी शौचालय लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई ... से आने वाले मुसाफिर अपने परिव... पहुंचते है तो उन्हें सबसे पह... तलाशने की मशक्कत करनी प... सवाल उठा रहे है कि जब क... सुधारने के लिए करोड़ों रुपये का... चल रहा है, तो सार्वजनिक सुविधा ... जरूरत पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा र... ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि निर्... दौरान अस्थायी शौचालय तत्काल स्थापित किए जाए, ताकि यात्रियों खासतौर पर महिलाओं की परेशानी दूर हो सके।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिटी साइड यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। स्वराज्य इंडिया में प्रमुखता से प्रकाशित खबर के असर के बाद डीआरएम के निरीक्षण के एक दिन बाद सिटी साइड स्थित 9 नंबर सुरंग के बाहर अस्थायी टॉयलेट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया।

गौरतलब है कि स्टेशन पर शौचालय की समुचित व्यवस्था न होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री मजबूरी में खुले में पेशाब करते थे। इससे स्टेशन परिसर की छवि खराब होने के साथ-साथ यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ती थी।

महिला यात्रियों को विशेष रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था और भीषण दुर्गंध के कारण लोग नाक-मुंह ढककर गुजरते थे।

स्वराज्य इंडिया द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे के प्रकाश में आने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया और डीआरएम के निरीक्षण के तुरंत बाद अस्थायी टॉयलेट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी।

स्थानीय यात्रियों का कहना है कि यह कदम देर से सही, लेकिन बेहद जरूरी था। अस्थायी व्यवस्था शुरू होने से गंदगी, दुर्गंध और असहज स्थिति में काफी राहत मिलेगी। यात्रियों ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में यहां स्थायी और बेहतर शौचालय व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। स्वराज्य इंडिया की पत्रकारिता एक बार फिर जनहित के मुद्दों पर असरदार साबित हुई।

माया बिल्डर को संरक्षण देने वाले कार्मिकों पर गिरेगी गाज!

शासन ने मांगी साठगांठ में शामिल अफसर-कर्मचारियों की रिपोर्ट

स्वराज इंडिया
खबर का असर

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शताब्दीनगर और जवाहरपुरम स्थित एफोर्डेबल आवासों में फायर फाइटिंग सिस्टम के 10 करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले में ब्लैकलिस्ट हो चुकी लखनऊ की माया बिल्डर फर्म को संरक्षण देने वाले केडीए के अधिकारियों-कर्मचारियों पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। शासन ने स्पष्ट निर्देश देते हुए घपले में शामिल कार्मिकों का विवरण, संस्तुति और आरोपपत्र सहित रिपोर्ट तलब की है। जांच में सामने आया कि माया बिल्डर फर्म ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर केडीए अफसरों की मिलीभगत से टेंडर हासिल किया। टेंडर प्रक्रिया के दौरान क्वालीफाइड फर्मों ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। शासन स्तर पर शिकायत पहुंचने के बाद सीडीओ दीक्षा जैन द्वारा कराई गई जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।

मुख्य अभियंता और लिपिकों की भूमिका संदिग्ध

जांच में आरोप है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता डीसी श्रीवास्तव और कुछ केडीए लिपिकों की मिलीभगत से माया बिल्डर को टेंडर आवंटित किया गया। फर्म के संचालक अश्वनी तिवारी के केडीए के कुछ कर्मचारियों से नजदीकी संबंध भी सामने आए हैं। उधर ब्लैकलिस्ट होने के बाद माया बिल्डर फर्म हाईकोर्ट पहुंच गई है। केडीए के कई अधिकारी-कर्मचारी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर फर्म को राहत मिलती है तो संरक्षण देने वाले अफसर भी बच सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि माया बिल्डर को प्राधिकरण स्तर से लेकर राजनीतिक संरक्षण तक हासिल रहा है। अब सबकी निगाहें शासन की अगली कार्रवाई और हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।

अनु सचिव का सख्त पत्र, फिर भी दबाने की कोशिश

सूत्रों के अनुसार, उप्र शासन के अनु सचिव चंद्रश्याम मिश्र ने 13 जनवरी 2026 को केडीए उपाध्यक्ष को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि 8 जुलाई 2025 को कमिश्नर कानपुर द्वारा भेजे गए संदर्भित पत्र पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि माया बिल्डर द्वारा की गई घपलेबाजी में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा विवरण, संस्तुति व आरोपपत्र सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए। बताया जा रहा है कि इस पत्र को भी केडीए स्तर पर दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वराज इंडिया www.swarajindianews.com
कानपुर सिटी
07

माया बिल्डर फर्म पर दर्ज होगी एफआईआर

केडीए में माया बिल्डर फर्म को बचाने वालों की लगेगी लंका!

जांच की जद में आएंगे और भी कर्मचारी

FOLLOW UP

स्वराज इंडिया में प्रकाशित खबर

10
करोड़ रुपए के फायर फाइटिंग टेंडर में किया गया फर्जीवाड़ा

ब्लैकलिस्ट की गई फर्म के पीछे अफसरों का संरक्षण उजागर

प्रेषक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
उपाध्यक्ष,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।
महोदय,
भवदीय,
अनु सचिव।

- 10 करोड़ के फायर फाइटिंग टेंडर में बड़ा घोटाला
- माया बिल्डर फर्जी अनुभव पत्र के आधार पर ब्लैकलिस्ट
- संरक्षण देने वाले केडीए कार्मिकों की रिपोर्ट शासन ने मांगी
- अनु सचिव का पत्र, फिर भी कार्रवाई लटकाने की कोशिश
- हाईकोर्ट गई फर्म, अफसर राहत आदेश के इंतजार में

शिकायतकर्ता ने खोली परतें

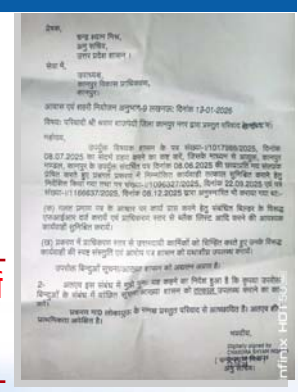

पनकी, कानपुर निवासी दिनेश सिंह ने शासन में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि 20 अगस्त 2020 को फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए निकाले गए टेंडर में एकता इलेक्ट्रिकल्स, कृष्णा रेफ्रिजरेशन, हर्ष कंस्ट्रक्शन, माया बिल्डर्स, रॉयल मेरीडियन, सुकाई इंजीनियर्स, यूपी डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन ने भाग लिया था। इसके बावजूद अर्हताएं पूरी करने वाली फर्मों को बाहर कर अनक्वालीफाइड माया बिल्डर को क्वालीफाई घोषित कर दिया गया।

ड्रोन से रेकी कर चोरी करने वाले तीन गिरफ्तार

स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर। बिठूर थाना क्षेत्र में चोरी की कई वारदातों का पुलिस ने बड़े पैमाने पर खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी करने से पहले ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके की रेकी करते थे। गिरोह का सरगना एक कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से ही 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से चोरी का सामान, औजार और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की है।

डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी सतर्कता के साथ ऐसे गिरोहों पर कार्रवाई कर रही है, ताकि इलाके में अपराध पर काबू पाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह चोरी से पहले इलाके की जाँच ड्रोन के जरिए करता था और उसके अनुसार वारदात को अंजाम देता था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से इरफ़ान सोलंकी को झटका, याचिका खारिज

प्रयागराज/कानपुर। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके द्वारा गैंगस्टर मामले में कानपुर ट्रायल कोर्ट में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2026 को याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने कानपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रद्द करने से इंकार किया। इरफ़ान सोलंकी ने 30 अगस्त 2025 के कानपुर कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में राज्य सरकार और पूर्व इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे को प्रतिवादी बनाया गया था। 25 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने इरफ़ान सोलंकी को जमानत दी थी। उनके भाई रिज़वान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला को भी जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद इरफ़ान सोलंकी जेल से बाहर आ चुके हैं।

- हाईकोर्ट ने इरफ़ान सोलंकी की याचिका खारिज की
- ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई रद्द नहीं होगी
- 26 दिसंबर 2022 की एफआईआर में गैंग लीडर बताया गया
- दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज
- जमानत मिलने के बाद भी कोर्ट ने मुकदमे की प्रक्रिया को जारी रखा

इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में उन्हें गैंग लीडर बताया गया। आरोप था कि इरफ़ान सोलंकी गैंग बना कर आम जनता को डराते थे और अपने गैंग के सहयोग से धन और संपत्ति अर्जित करते थे। उनके खिलाफ दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।एफआईआर तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे द्वारा दर्ज कराई गई थी।

इरफ़ान सोलंकी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, विनीत विक्रम और मोहित सिंह ने पैरवी की। सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल और रूपक चौबे ने दलीलें पेश की।

जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब कानपुर ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही यथावत जारी रहेगी। इरफ़ान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में कोई राहत नहीं मिली है।

धर्मान्तरण से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान

मेरा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है; वीडियो बना युवक ने दी जान, परिजनों का सड़क पर हंगामा

- मरने से पहले युवक ने एक वीडियो की थी पोस्ट।
- वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
- पूरा मामला पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत
- घर में भूत देखकर युवक ने फांसी लगाकर की थी खुदकुशी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। पनकी के युवक ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मैं अपने धर्म के रस्ते चलूंगा...पूरे देश में इस तरह का काम हो रहा है। बोलकर पनकी रतनपुर में युवक ने गुरुवार सुसाइड कर लिया। हालांकि पहले परिजनों ने अंधविश्वास के चलते सुसाइड करने की बात कही थी, लेकिन युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अब धर्म परिवर्तन की चर्चाएं होने लगी हैं।

परिजनों ने शव सड़क पर रखकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।

रतनपुर निवासी रोहित सिंह ने गुरुवार को फंदा लगाकर जान दे दी थी। परिजनों ने बताया था कि युवक की पिछले एक सप्ताह से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह मकान बेंच कर कहीं और रहने की बात कर रहा था।

वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया

वहीं घटना के दूसरे दिन मृतक युवक का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो बोल रहा है कि मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मैं अपने धर्म के रस्ते चलूंगा...पूरे देश में इस तरह का काम हो रहा है। युवक जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसने किसी का नाम नहीं लिया।

बहन ने बताई लखनऊ की घटना

मृतक की बहन निशा सिंह ने बताया कि भाई रोहित 26 जनवरी को छोटी बहन के घर लखनऊ गया था। तब उन्नाव से लखनऊ के चार बाग तक काल रिसीव नहीं हुई थी। बहन के घर पहुंच कर उसने रोते हुए जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात बताई थी। उसने बताया था कि चार लोग ट्रेन में मिले थे, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और चार बाग में एक मजार पर भी ले गए थे।

तहरीर के आधार पर की जाएगी कार्रवाई

परिजनों ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद परिजनों ने शव को घर के पास चौराहे पर रखकर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराने के प्रयास में जुटी है। पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि युवक का वीडियो सामने आया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

जनगणना 2027 की तैयारी तेज, कानपुर में 13 हजार से अधिक कार्मिक होंगे तैनात

22 मई से 20 जून तक चलेगा पहला चरण, दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना की समयसीमा, कार्ययोजना और डिजिटल प्रक्रिया को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जनगणना का पहला चरण 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक संचालित होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। जनपद में जनगणना कार्य के लिए कुल 13,089 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी।

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि जनगणना 2027 देश की 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। यह गांव, शहर और वार्ड स्तर पर प्राथमिक आंकड़ों का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय स्रोत मानी जाती है। जनगणना के माध्यम से आवास की स्थिति, मूलभूत सुविधाएं, परिसंपत्तियां, जनसांख्यिकीय विवरण, धर्म, भाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियां, प्रवासन और उर्वरता से संबंधित सूक्ष्म स्तर का डेटा प्राप्त होता है।

बताया गया कि पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी।

इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। पहली बार नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी दिया गया है। जनगणना से पहले 15 दिनों की अवधि में नागरिक सेंसस सेल्फ एन्युमरेशन पोर्टल एवं एप के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। कोई भी सामान्य निवासी ऑनलाइन प्रश्नावली भरकर स्वगणना कर सकता है।

घर-सूचीकरण चरण के दौरान सर्वेक्षक भवन के उपयोग, निर्माण सामग्री, कमरों की संख्या, स्वामित्व की स्थिति, जल, विद्युत और शौचालय की उपलब्धता, खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन, फोन, वाहन और टेलीविजन जैसी परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रकार की जानकारियां दर्ज करेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 28 फरवरी तक, फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण 31 मार्च तक तथा प्रगणक और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण हर हाल में 15 मई तक पूरा कर लिया जाए। बैठक में लखनऊ से आए सहायक निदेशक सेंसस दिनेश यादव ने जनगणना प्रक्रिया को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी,

अपर नगर आयुक्त आवेश खान, जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत सिंह, डीआईओ शांतनु श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी ईशा शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

चलने-फिरने में लाचार वृद्धा की अलाव से जिंदा जलकर मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। बिधनू थानाक्षेत्र के ओरियारा चौराहे के पास हाईवे पर स्थित एक ईंट-भट्ठे में गुरुवार देर शाम अलाव से बिस्तर पर सो रही 70 वर्षीय कलावती की जिंदा जलकर मौत हो गई।

महिला चलने-फिरने में पूरी तरह लाचार थीं। घटना के समय उनके पति बलराम चौहान (72) पास के बाजार में सामान खरीदने गए हुए थे।

मूल रूप से बिहार के रहने वाले बलराम चौहान पिछले दो वर्षों से ईंट-भट्ठे में मुनीम का काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि चार महीने पहले वह चलने-फिरने में असमर्थ अपनी पत्नी कलावती को बिहार से अपने साथ भट्ठे पर स्थित कमरे में ले आए थे। गुरुवार शाम को कलावती चारपाई पर लेटी हुई थीं और सर्दी से बचने के लिए पास में एक तसले में अलाव जल रहा था। वह शाम करीब 7:30 बजे माधवबाग बाजार से सामान लेने गए थे। इसी दौरान चारपाई के बिस्तर में

अचानक आग लग गई। कमरे से धुआं निकलता देख भट्ठा कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग बुझने तक कलावती की जलकर मौत हो चुकी थी। बिधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि महिला की चारपाई के पास

अलाव जल रहा था जिससे बिस्तर में आग लगी। पति की ओर से कोई आरोप नहीं है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सम्पादकीय

आर्थिक सर्वेक्षण ने लचीलापन पर दिया जोर

अति आशावाद से बचें देश में आम बजट से पहले सामने आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला व गतिशील बनाने पर बल दिया गया है। यह सर्वेक्षण उन चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है, जिनके लिए सावधानीपूर्वक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद दर यानी जीडीपी के 7.4 रहने का भरोसा जताया गया है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकास वृद्धि दर के 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान में सीमापरक तनाव, व्यापार में व्यवधान और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को भी ध्यान में रखा गया है। निश्चित रूप से यह सावधानीपूर्वक दर्शाया गया आशावादी दृष्टिकोण घरेलू मांग, उपभोग और निवेश की मजबूती को ही दर्शाता है। इसके बावजूद कि तमाम बाहरी जोखिम विद्यमान हैं, मसलन टैरिफ को लेकर आपूर्ति श्रृंखला में तनाव व देश की अपेक्षाओं का संतुलन बनाना शामिल है। यह सार्थक है कि सर्वेक्षण यथार्थवाद को नजरअंदाज नहीं करता है, जो यह भी दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पूंजी प्रवाह व मुद्रा की ताकत से ही सफलता सुनिश्चित नहीं होती। यह भी हकीकत है कि एआई जैसी नई तकनीकों से होने वाले लाभ असमानता को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसके लिये भी सहायक मानव संसाधन और विनियामक ढांचे की जरूरत होती है। खासकर भारत जैसे देश में जहां श्रम शक्ति का बाहुल्य है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश होने का लाभ उठाएं। इसके लिये कौशल विकास को प्राथमिकता देने की सख्त जरूरत है, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी उत्पादों के जरिये विश्व में आर्थिक स्पर्धा का मुकाबला कर सकें। ये कदम हमारे निर्यात बढ़ाने में भी सहायक हो सकते हैं। कालांतर में ये हमारे व्यापार घाटे को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है।

इसमें दो राय नहीं है कि हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के जरिये एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके अंतर्गत स्वदेशी अभियान को तरजीह देने से लेकर रणनीतिक लचीलेपन और रणनीतिक अनिवार्यता भारत की आर्थिक क्षमता की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं की साख को अंतर्राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप बनाया जाए। निस्संदेह , विश्व में भारतीय उत्पाद 'खरीदने के बारे में सोचने' से स्थिति को 'बिना सोचे भारतीय उत्पाद खरीदने' वाली सोच विकसित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इस स्थिति के लिये हमें विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता की सख्त जरूरत होगी। निस्संदेह, हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ संपन्न हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर अर्थव्यवस्था में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसके अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से लटके हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। सर्वेक्षण में इस बाबत कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में इस एफटीए के सिरे चढ़ने की उम्मीद है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी को कितना मिलता है।

सवाल यह भी है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ आम आदमी के जीवन को बदलने में कितना मददगार होगा।

एआई और तकनीक क्रांति के दौर में भारतीय विपुल श्रम शक्ति का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है। भारत दुनिया में सबसे युवा श्रम शक्ति वाला देश है तो क्या हम उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप रोजगार देने में सक्षम होंगे, ताकि वे विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दे सकें।

नाइट्रोजन चक्र बदलाव से अन्न-पेयजल संकट

पुष्परंजन

नया अध्ययन बताता है नाइट्रोजन चक्र परिवर्तन खाद्य उत्पादन, पानी की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जलवायु स्थिरता को गहरे तक प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी पर कई परिवर्तन कर दिए हैं। इनमें से कई परिवर्तन...नया अध्ययन बताता है नाइट्रोजन चक्र परिवर्तन खाद्य उत्पादन, पानी की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जलवायु स्थिरता को गहरे तक प्रभावित कर रहा है।जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी पर कई परिवर्तन कर दिए हैं। इनमें से कई परिवर्तन ऐसे हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं। बढ़ती गर्मी, बारिश के पैटर्न में बदलाव और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊंचे स्तर से फसलों को होने वाला नुकसान हमें दिखाई देता है लेकिन जलवायु के परिवर्तन समूची खाद्य प्रणालियों को कितना प्रभावित कर रहे हैं, इसका जरा भी अंदाजा हमें नहीं है। मिट्टी की सतह के नीचे और पौधों के ऊत्तकों के अंदर चुपचाप परिवर्तन हो रहा है। भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन की हलचल अब बदली हुई जलवायु परिस्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर रही है। नाइट्रोजन में ये परिवर्तन खाद्य उत्पादन, पानी की सुरक्षा,पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और जलवायु स्थिरता को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर जीवन चक्र में नाइट्रोजन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह तत्व नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम और आनुवंशिक सामग्री बनाकर जीवन को सहारा देता है।

पौधे पत्तियों,जड़ों और अनाज को उगाने के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। मिट्टी के जीवाणु जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रोजन को उपयोग योग्य रूपों में बदलते हैं।

नाइट्रोजन का संतुलित प्रवाह स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र और अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त नाइट्रोजन हवा और पानी में चला जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और गर्मी बढ़ाने वाली ग्रीनहाउस गैसें बनती हैं। दूसरी ओर,नाइट्रोजन की सीमित उपलब्धता फसलों के विकास को धीमा करने के साथ-साथ खाद्य आपूर्ति को भी कम कर देती है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन चक्र के बारे में एक नए अध्ययन में चीन के जेजान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मियाओ चंग का कहना है कि गर्म होती दुनिया में नाइट्रोजन खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक निर्णायक कारक बनती जा रही है। यह अध्ययन दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन नाइट्रोजन चक्रों को इस तरह से बदल रहा है जो या तो सतत विकास का समर्थन कर सकता है या पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण सीमाओं से परे धकेल सकता है। वैज्ञानिकों ने वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र मॉडल के साथ फील्ड में 30 वर्षों के प्रयोगों का विश्लेषण किया। उन्होंने इसमें विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में फसल भूमि, जंगलों और घास के मैदानों को सम्मिलित किया। उन्होंने उर्वरक, खाद, वायुमंडलीय जमाव और जैविक स्थिरीकरण के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ने वाली नाइट्रोजन पर गौर किया। फसल कटाई, गैस उत्सर्जन के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर निकलने वाली नाइट्रोजन को भी मापा गया। इस विश्लेषण के असमान परिणाम सामने आए। कुछ स्थानों पर विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों में उत्पादकता में वृद्धि देखी गई जबकि अन्य क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी, प्रदूषण और पैदावार में कमी का अनुभव हुआ। नाइट्रोजन की असमान प्रतिक्रियाएं अब खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में वैश्विक अंतर को गहरा कर रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता नाइट्रोजन को प्रभावित करती है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उच्च स्तर प्रकाश संश्लेषण में सुधार करके पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। गेहूं, चावल, मक्का और सोयाबीन सहित प्रमुख फसलों में अक्सर अधिक पैदावार देखी जाती है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की स्थितियों में जंगल और घास के मैदान भी पौधों की सामग्री का अधिक उत्पादन करते हैं। पानी के इस्तेमाल की बेहतर क्षमता पौधों को हल्के सूखे के स्ट्रेस से निपटने में मदद करती है। लेकिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने पर पौधों के टिशू में नाइट्रोजन कम होती है। अनाज में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसका पोषण मूल्य कम हो जाता है। पत्तियों और तनों में भी नाइट्रोजन की कमी दिखती है। दलहनी फसलें गैर-दलहनी प्रजातियों की तुलना में नाइट्रोजन की कमी का बेहतर प्रतिरोध करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लंबे समय तक नाइट्रोजन की कमी भविष्य की ग्रोथ और कार्बन स्टोरेज की क्षमता को कमजोर कर सकती है।अध्ययन के सह-लेखक बाओजिंग गु ने कहा, ज्यादा कैलोरी का मतलब अपने आप बेहतर पोषण नहीं होता है। हम शायद ज्यादा बायोमास काट रहे हैं, लेकिन प्रति यूनिट नाइट्रोजन कम है, जो इंसानों के खाने और जानवरों के चारे दोनों के लिए मायने रखती है। गर्मी नाइट्रोजन के नुकसान को बढ़ाती है।

अजित पवारः आरोपों से ऊपर उठे राजनीति के 'दादा-पुरुष'

राजनीतिक जीवन

डा0 सुधीर कुमार

अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं।यह खबर केवल एक व्यक्ति के निधन की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग के अचानक थम जाने की सूचना है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया।

जिस नेता को लोग अधिकार, अनुभव और निर्णय क्षमता का पर्याय मानते थे, उसका इस तरह अचानक चले जाना सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है। एक संभावनाओं भरी महाराष्ट्र की राजनीति एवं राष्ट्रीय विचारों का सफर ठहर गया, उनका निधन न केवल महाराष्ट्र के लिये, भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिये बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति पर एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सहकारी आन्दोलन को भी गहरा धक्का लगा है।अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं। औपचारिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रही, किंतु जीवन की व्यावहारिक पाठशाला ने उन्हें वह सिखाया जो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान भी नहीं सिखा पाते। शायद यही कारण रहा कि अजित पवार की राजनीति किताबों से नहीं, जमीन से निकली हुई राजनीति थी, जिसमें किसानों की पीड़ा, सहकारी संस्थाओं की

ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज साफ दिखाई देती थी। राजनीति में उनका प्रवेश किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सहकारी आंदोलन की प्रयोगशाला से हुआ। 1982 में मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। यह वही दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाएं सत्ता की रीढ़ मानी जाती थीं। अजित पवार ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि ग्रामीण महाराष्ट्र को साधना है तो उसे बैंक, चीनी मिल, सिंचाई और बिजली से जोड़ना होगा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1991 अजित पवार के राजनीतिक जीवन का निर्णायक वर्ष रहा। पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने वित्तीय प्रशासन और संगठन संचालन में अपनी दक्षता का परिचय दिया। सोलह वर्षों तक इस पद पर बने रहना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और पकड़ को दर्शाता है। उसी वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित होना उनके बढ़ते कद का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। यह फैसला केवल पारिवारिक निष्ठा का नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरदृष्टि का भी उदाहरण था। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश और फिर लगातार बारामती से जीत ने उन्हें जनाधार का वह आधार दिया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में विरले ही कोई चुनौती दे सका। अजित पवार को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे कठिन और संवेदनशील विभागों को संभालते हुए उन्होंने विकास और विवाद दोनों को नजदीक से जिया। जल संसाधन मंत्री के रूप में कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा। इन परियोजनाओं ने जहां किसानों के लिए पानी और उम्मीद का संदेश दिया, वहीं आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर रखा। इसके बावजूद वे उन नेताओं में रहे जो फाइलों से नहीं, फैसलों से पहचाने जाते थे। उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा अध्याय है। छह बार इस पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक संयोग नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन, गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक ताकत का परिणाम था। वे सरकार में अक्सर संकटमोचक की भूमिका में दिखे।

बजट, वित्तीय प्रबंधन और संसदीय रणनीति में उनकी पकड़ ऐसी थी कि विरोधी भी उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वाकांक्षी कहा गया, कभी-कभी कठोर और रूखे स्वभाव का नेता भी बताया गया, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता की वास्तविकता को वे भावनाओं से नहीं, निर्णयों से देखते थे। विवाद उनके राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे। सिंचाई घोटाले से लेकर बयानबाजी तक, कई मौके ऐसे आए जब उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लगे। ÷अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें?÷ जैसे बयान ने उन्हें आलोचनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने माफी भी मांगी।

टीचर्स सेल्फ केयर टीम ने दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को दी एक करोड़ की मदद

11 दिनों में खातों तक पहुंची धनराशि, 4050 शिक्षकों के सहयोग से बनी मिसाल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। टीचर्स सेल्फ केयर टीम (टीएससीटी) ने आपसी सहयोग और संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल पेश करते हुए कानपुर नगर के दो दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को कुल एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह राशि प्रदेश स्तर पर इस माह दिवंगत 20 सदस्यों के परिवारों को दी गई कुल 10 करोड़ रुपये की सहायता का हिस्सा है।

जिला संयोजक सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि आवास विकास-3 निवासी स्वर्गीय संजय कुमार, जो प्राथमिक विद्यालय तिलकनगर द्वितीय (प्रेम नगर) में कार्यरत थे, तथा कल्याणपुर निवासी स्वर्गीय नीतू सिंह पाल, जो प्राथमिक विद्यालय इनायतपुर (जनपद कन्नौज) में शिक्षिका थीं, टीचर्स सेल्फ केयर टीम की सक्रिय सदस्य थीं। दोनों के निधन के बाद मात्र 11 दिनों के भीतर उनके नामितों के बैंक खातों में सहायता राशि भेज दी गई।

दिवंगत शिक्षकों को श्रद्धांजलि दी गई

कानपुर मंडल संयोजक जितेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश के 3 लाख 20 हजार 800 से अधिक सदस्य इस अभियान से जुड़े हैं। किसी सदस्य के निधन की सूचना मिलने पर जिला इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर प्रदेश इकाई को भेजे जाते हैं, जिसके बाद तय समय में सहायता राशि नामितों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है।

जिला मीडिया प्रभारी अनूप कुमार यादव के अनुसार, अब तक उत्तर प्रदेश में 396 दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को लगभग 217 करोड़ 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

हर माह नियमित रूप से 20 दिवंगत सदस्यों के परिवारों को यह सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इससे पूर्व भी कानपुर नगर के कई शिक्षकों के परिजनों को 50 लाख रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है।

यह भी जान लीजिए

- कानपुर नगर के 4050 सदस्यों के सहयोग से पूरी हुई सहायता प्रक्रिया
- प्रदेश भर में इस माह 20 दिवंगत सदस्यों के परिजनों को 10 करोड़ रुपये की मदद
- प्रति सदस्य मात्र 15.50 रुपये के ऑनलाइन योगदान से जुटाई गई राशि
- टीएससीटी से जुड़े हैं बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, डायट, शिक्षामित्र, अनुदेशक, लिपिक व अधिकारी
- गंभीर बीमारी, उपचार और बेटियों के विवाह में भी संगठन करता है सहयोग

बिजली पोल में उतरे करंट से भैंस की मौत, ग्रामीण गुस्साए

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

चौबेपुर/बिल्हौर (कानपुर)। चौबेपुर के भऊआपुर गांव में गुरुवार सुबह बिजली के पोल में करंट उतरने से एक भैंस की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पशु पालक को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर कई घंटे तक हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्साधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई और मुआवजे का भरोसा दिलाया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए।

जानकारी के अनुसार गांव निवासी सुनील राजपूत सुबह अपनी भैंस को घर से कुछ दूरी पर स्थित प्लॉट की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान सड़क किनारे लगे बिजली के पोल में करंट होने के कारण भैंस चपेट में आ गई और मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित पशु पालक का कहना है कि भैंस की कीमत करीब

⇨ भऊआपुर गांव में हादसा, मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हंगामा

80 हजार रुपये थी।घटना से नाराज ग्रामीणों ने गांव के मुकेश और रामजीवन के नेतृत्व में मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए एहतियातन बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे करीब पांच घंटे तक गांव की सप्लाई प्रभावित रही। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्साधिकारी मनीष ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए नमूने लिए और नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। उधर, उपखंड अधिकारी देवव्रत आर्य ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व पति पर निजी तस्वीरें वायरल करने का आरोप, एफआईआर दर्ज

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। ककवन थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पूर्व पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। महिला का आरोप है कि पूर्व पति ने उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे, उसके वर्तमान पति और मासूम बच्चे को जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र स्थित मिथलेशपुर गांव की निवासी है। तहरीर के अनुसार, करीब पांच वर्ष पूर्व उसकी शादी ककवन थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो गया। हालात बिगड़ने पर पारिवारिक

⇨ विरोध करने पर वर्तमान पति और मासूम बच्चे को जान से मारने की धमकी

हस्तक्षेप के बाद दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध समाप्त हो गए।

इसके बाद महिला ने अपने ही गांव के एक युवक से दूसरी शादी कर ली और वर्तमान में उसी के साथ रह रही है। आरोप है कि चार दिन पूर्व पूर्व पति ने बदले की भावना से महिला की पुरानी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दीं।

महिला का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- पूर्व पति पर निजी तस्वीरें वायरल करने का गंभीर आरोप
- विरोध करने पर वर्तमान पति और बच्चे को जान से मारने की धमकी
- पहले विवाह में उत्पीड़न के बाद आपसी सहमति से हुआ था अलगाव
- तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज, पुलिस की जांच जारी

स्वच्छता, शवदाह और संपर्क मार्ग की बदहाली पर उठे सवाल

नानामऊ घाट पर गंदगी और अव्यवस्था, सपा ने प्रशासन को घेरा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर ब्लॉक के नानामऊ स्थित गंगा घाट की बदहाल स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कड़ा सवाल खड़ा किया है। सपा के विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने घाट का निरीक्षण कर स्वच्छता, शवदाह सुविधाओं और संपर्क मार्ग की जर्जर हालत को गंभीर लापरवाही बताया।

निरीक्षण के बाद विनय यादव ने कहा कि घाट परिसर में गंदगी फैली है और कूड़े के नियमित निस्तारण की कोई प्रभावी व्यवस्था नजर नहीं आती। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और शुल्क वसूली के सरकारी दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात संतोषजनक नहीं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की 'नमामि गंगे' योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि भारी बजट खर्च होने के दावों के बावजूद नानामऊ घाट पर ठोस परिणाम नहीं दिख रहे।

सपा नेता ने शवदाह सुविधाओं की कमी को भी प्रमुख समस्या बताया। विद्युत शवदाह गृह का अभाव, शवों के निस्तारण व पंजीकरण की समुचित व्यवस्था न होना अव्यवस्था को बढ़ा रहा है।

साथ ही घाट तक पहुंचने वाला संपर्क मार्ग संकरा व क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालुओं और अंतिम संस्कार में आने वालों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

सफाईकर्मियों की नियमित तैनाती न होना प्रशासनिक अनदेखी का संकेत बताया गया। निरीक्षण के बाद विनय यादव ने कहा कि प्रशासन को समस्याओं से लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा। चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सुधार नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी जनहित में आंदोलन करेगी।

दो महीने से गांव में नहीं पहुंचा पानी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

जेई के आश्वासन के बावजूद नहीं सुधरी लीकेज पाइपलाइन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हमीरपुर। मुस्कुरा विकास खंड की ग्राम पंचायत निवादा से सम्बद्ध विभूनी मजरा में पिछले दो महीनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। गांव की आबादी लगभग चार सौ है, लेकिन यहां केवल दो हैंडपंप ही जल का सहारा हैं, जिनसे अत्यधिक दोहन के चलते वे भी अक्सर खराब हो जाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। गांव के दिलीप, प्रदीप, अनुज, जाल मुहम्मद, सब्बीर अहमद, बाबूलाल, पप्पू गोस्वामी और रशीद ने बताया कि दिसंबर माह में जेई शंकु कुमार ने पाइपलाइन लीकेज ठीक कराने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों ने बताया कि विभूनी से लगभग तीन किलोमीटर दूर नमामि गंगे परियोजना की पानी की टंकी स्थित है, जिससे गांव को जलापूर्ति होती है। इसी मार्ग में कई स्थानों पर पाइपलाइन फट जाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी महीनों तक ध्यान नहीं देते, जिससे हर बार जल संकट गहरा जाता है।

इसी तरह ग्राम बिवांर के कैथानी मोहल्ला में भी नमामि गंगे परियोजना की पाइपलाइन कई स्थानों पर फटी हुई है। लीकेज के कारण रास्तों पर कीचड़ फैल गया है, जिससे लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। यहां भी जेई द्वारा मरम्मत का आश्वासन दिया गया था, लेकिन दो सप्ताह बीतने के बाद भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है खेलकूद

» उमंग महोत्सव के तीसरे दिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन

» विभिन्न खेलों में बच्चों ने उत्साहपूर्वक लेकर दिखाई अपनी प्रतिभा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। खेलकूद से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। यह विचार आरपीएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डीपी शुक्ला ने खेलकूद प्रतियोगिता का टॉस कराते हुए व्यक्त किए।

रसूलाबाद स्थित स्नेहलता गुप्ता मेमोरियल डिग्री कॉलेज में चल रहे वार्षिक कार्यक्रम उमंग महोत्सव के अंतर्गत तीसरे दिन विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ कबड्डी प्रतियोगिता के टॉस के साथ किया गया।

छात्राओं की खो-खो प्रतियोगिता में बीएससी की कप्तान लक्ष्मी की टीम विजेता रही, जबकि बीएससी प्रथम वर्ष की कप्तान अक्षरा की टीम उपविजेता बनी। वहीं छात्रों के बीच आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र ऋतिक की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा एमए प्रथम वर्ष के छात्र नंद किशोर की टीम उपविजेता रही।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कॉलेज के प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता सराग, उप प्रबंधक प्रवेश कुमार यादव (छुन्नू), क्रीडाध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी (जीतू) सहित दुर्गेश त्रिपाठी, सिद्ध राम राजपूत, आलोक वर्मा, विमल यादव, सीके त्रिपाठी, राजीव राजपूत, अजीत कुमार गुप्ता, सचिन कटियार, डॉ. अनुराधा, संतोष बाजपेई, आरएन शुक्ला, दिनेश राजपूत, विवेक पांडेय आदि उपस्थित रहे।

सरकारी निधि हड़पने वाले हसनापुर प्रधान की शपथपत्र में हुई शिकायत

ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हसनापुरग्राम प्रधान की बढेंगी मुसीबतें

» स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। भ्रष्टाचार को लेकर अकबरपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत हसनापुर के ग्राम प्रधान की मुसीबतें बढने वाली हैं। ग्राम सभा के कई सरकारी बिल बाउचर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो लाखों की हेराफेरी उजागर हुई। इस प्रकरण में स्वराज इंडिया ने विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। भ्रष्टाचार को लेकर गांव वालों ने भी खुलकर आवाज उठाई है। ग्राम प्रधान सहित अन्य सरकारी कर्मियों द्वारा किए घोटाले की जांच के लिए शपथपत्र में प्रार्थनापत्र सीडीओ को दिया गया है।

- एडीओ की ओर से ग्राम प्रधान राम सिंह यादव और ग्राम सचिव को जारी स्पष्टीकरण पत्र का जवाब नहीं दिया गया
- ग्राम प्रधान ने अपने और सगे संबंधियों के नाम पर बैंक खाते में ट्रांसफर करवाई लाखों की ग्राम विकास निधि
- खडंजा, नाली निर्माण, हैंडपंप मरम्मत सहित कई अन्य मदों पर खर्च दिखाकर किया गया सरकारी धन का बंदरबांट

तत्कालीन सीडीओ एन लक्ष्मी के निर्देश पर अकबरपुर ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी आदित्य शुक्ला ने 10 दिसंबर 2025 को ग्राम प्रधान राम सिंह यादव और ग्राम सचिव को पत्र जारी करके सरकारी निधि की राशि अपने खातों में ट्रांसफर को लेकर बिंदुवार जवाब तलब किया था लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत की वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव शशि बाजपेई ने यह कहकर किनारा करने का प्रयास किया था कि यहां पर ग्राम सचिव के तौर पर अगस्त सितंबर में आई हूं, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं, ग्राम सचिव ने भी अबतक कोई रिपोर्ट विभाग को नहीं दी है। ग्राम प्रधान राम सिंह यादव पर सरकारी धन गबन के गंभीर आरोप हैं, मामले में वह घिरते जा रहे हैं। इनपर सख्त कार्रवाई की तैयारी है।

ग्राम पंचायत पोर्टल से जारी स्क्रीन शॉट के अनुसार वर्ष 2023-2024 में 1 जून 2023 को ग्राम प्रधान के खाते में 21 हजार 5 सौ का भुगतान साफ सफाई के लिए दिखाया गया है। 6 अगस्त 2023 को प्राथमिक विद्यालय ठकुरनगढेवा में शौचालय निर्माण के लिए 17 हजार 410 का भुगतान किया गया है। 31 दिसबंर 2022 को जगद सिंह के घर से मेवालाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य में 29 हजार 930 रूपए का भुगतान ग्राम प्रधान के खाते में किया गया है। 6 अगस्त 2023 को हैंडपंप मरम्मत के नाम पर 5400 का भुगतान लिया गया है। इस तरह से कई अन्य भुगतान हैं जिनको नाते रिश्तेदारों के खाते में डलवाकर हडपा गया है। इस मामले में गांव के ही निवासी सौरभ यादव पुत्र कन्हैयालाल ने सीडीओ कानपुर देहात को शपथपत्र में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है। सौरभ सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान ने सरकारी निधि हडप ली है, जिससे गांव का विकास प्रभावित हुआ है। इस मामले में सचिवों की भूमिका भी गडबड है। उनपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

सीडीओ विधान जायसवाल ने कहा कि प्रकरण की जानकारी कर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होगी।

जमीन विवाद से परेशान किसान ने फांसी लगा कर दी जान

» धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने और धमकियों से था मानसिक तनाव में

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना के अमरौधा जुलैठी निवासी किसान राकेश कुमार संखवार ने जमीन संबंधी धोखाधड़ी और लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां सावित्री देवी ने आत्महत्या किए जाने की पुष्टि की है।मृतक के भतीजे सोनू ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि राकेश के पास दो प्लॉट थे। एक प्लॉट पहले ही बिक चुका था, जबकि दूसरे प्लॉट को लेकर अशोक पुत्र ठाकुर से बातचीत चल रही थी। आरोप है कि चार महीने पूर्व अशोक राकेश को तहसील भोगनीपुर ले गया और धोखाधड़ी से प्लॉट के साथ-साथ डेढ़ बीघा कृषि भूमि भी अपने नाम करा ली। परिजनों को जब इस गड़बड़ी की जानकारी हुई तो उन्होंने राकेश से पूछताछ की।

राकेश ने बताया कि उसने केवल प्लॉट ही बेचा था। इस संबंध में जब अशोक से सवाल किया गया तो उसने जान से मारने की धमकी दी और दोबारा घर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। परिजनों का कहना है कि जमीन हड़प लिए जाने और धमकियों के चलते वह गहरे अवसाद में चले गए, जिसके कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर संजय कुमार वर्मा ने बताया कि परिजनों द्वारा जमीन विवाद की बात कही जा रही है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

मानकों पर खरे न उतरने वाले स्कूली वाहन तत्काल हटाएं

बिना नम्बर प्लेट व ओवरलोड वाहन के लिए शुरू करें अभियान: डीएम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट स्थित मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार में की गई। बैठक में डीएम का सख्त रुख नजर आया। उन्होंने कहा कि बिना नंबर प्लेट व ओवरलोड वाहन पर अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुधार, ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन तथा जन-जागरूकता अभियानों की समीक्षा भी की।

जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा राहवीर योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मदद करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की अनावश्यक पुलिस कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

डीएम ने हाईवे व प्रमुख मार्गों के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि चौराहों, विद्यालयों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप और रिफ्लेक्टर युक्त साइनेज लगाए जाएं। चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर शीघ्र सुधारात्मक कार्य कराने के भी निर्देश दिए गए।

परिवहन विभाग को बिना नम्बर प्लेट, ओवरलोड और गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया। हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अनिवार्य बताते हुए प्रभावी चालान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्कूली वाहनों की सुरक्षा पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने सभी विद्यालय वाहनों की नियमित फिटनेस जांच, चालकों के लाइसेंस सत्यापन और स्पीड गवर्नर की जांच कराने के निर्देश दिए। मानकों पर खरे न उतरने वाले वाहनों को तत्काल संचालन से बाहर करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही गोल्डन ऑवर में राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए। सड़क सुरक्षा माह के दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों व ग्राम पंचायतों में शपथ, रैली, नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, दुष्यंत कुमार मौर्य सहित पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बंद पड़ी फैक्ट्री से 50 लाख का गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

रनियां पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरगना मौके से हुआ फरार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रनियां थाना पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रायपुर चौराहे के पास बिक्री के लिए खड़े दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री से करीब 95 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी जा रही है। कार्रवाई के दौरान तस्करी गिरोह का सरगना मौके से फरार हो गया।

रायपुर चौराहे पर दो युवक प्लास्टिक के टब और बाल्टी की फेरी लगाने के बहाने खड़े थे। संदिग्ध गतिविधियों को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर रनियां शिवनारायण सिंह ने जब पूछताछ की तो दोनों घबरा गए। तलाशी लेने पर उनके पास गांजा मिलने से पुलिस और स्थानीय लोग चौंक गए। पकड़े गए तस्करों में आर्यन सिंह, निवासी सचेंडी व अनुज कुमार निवासी हरजेंदर नगर, लाल बंगला थाना चकेरी कानपुर हैं। जबकि सरगना धारा सिंह, निवासी पतारा, घाटमपुर फरार हो गया।

पूछताछ में आरोपियों ने गांजा तस्करी की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने पहाड़पुर रोड स्थित रिंद नदी किनारे कानपुर नगर निवासी जितेंद्र कुमार की बंद पड़ी फैक्ट्री में छापेमारी की। पुलिस के पहुंचते ही तस्करी गिरोह का सरगना पीछे के रास्ते से फरार हो गया। फैक्ट्री से चार झालों में पैक 90 गांजा पैकेट बरामद किए गए। सूचना पर सीओ सदर संजय कुमार सिंह और एसओजी प्रभारी जेपी शर्मा भी मौके पर पहुंचे। बरामद गांजे का वजन कराया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। इंस्पेक्टर रनियां ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। फरार सरगना की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।

बेकाबू डेयरी पिकअप खाई में पलटी, बड़ा हादसा टला

» रसूलाबाद में नहीं थम रही डेयरी पिकअप की रफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार डेयरी पिकअप हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में पिकअप चालक को मामूली चोटें आईं, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

घटना रसूलाबाद थाना क्षेत्र के माधव नगर भैसायां गांव के सामने की है। बताया गया कि पाल नगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार डेयरी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में लदी दूध की केन सड़क पर गिरने से सारा दूध फैल गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि रसूलाबाद क्षेत्र में इन दिनों डेयरी पिकअप की रफ्तारों पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। तेज गति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। करीब एक माह पूर्व रसूलाबाद कस्बे के कानपुर मार्ग स्थित केशव नगर में तेज रफ्तार डेयरी पिकअप की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से डेयरी पिकअप की रफ्तार पर सख्ती से नियंत्रण लगाने और नियमित चेकिंग की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

पुखरायां को मिलेगी नई पहचान खुलेगा नीलगिरी वाटर पार्क

झांसी हाईवे के किनारे जल्द शुरू होगा निर्माण

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात।कानपुर देहात जनपद के पुखरायां क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। झाँसी हाईवे के किनारे यह पार्क बनने की तैयारी की जा रही है. नीलगिरी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, जिसकी प्रोपराइटर रीना सिंह भदोरिया पत्नी श्याम सिंह हैं, को पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। लगभग ?3 करोड़ की पूंजी लागत से बनने वाला यह वाटर पार्क एवं रिजॉर्ट पुखरायां को पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगा।

इस परियोजना के शुरू होने से पुखरायां और आसपास के क्षेत्रों के बच्चों व परिवारों को अब मनोरंजन के लिए कानपुर या लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक, सुरक्षित और विश्वस्तरीय वाटर पार्क की सुविधा उपलब्ध होगी। खास तौर पर बच्चों के लिए यह पार्क आकर्षण का केंद्र बनेगा।

नीलगिरी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट में बच्चों एवं बड़ों के लिए अलग-अलग वाटर स्लाइड्स, स्विमिंग पूल, किड्स ज़ोन, फूड कोर्ट, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था तथा भविष्य में ठहराव हेतु रिजॉर्ट सुविधा प्रस्तावित है। यह परियोजना न केवल मनोरंजन का साधन बनेगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी।

परियोजना की प्रोपराइटर रीना सिंह भदोरिया ने बताया कि उनका उद्देश्य पुखरायां को एक आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे क्षेत्र के बच्चों को बेहतर सुविधाएँ मिलें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

पर्यटन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। नीलगिरी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट के खुलने से पुखरायां को एक नई पहचान मिलेगी और यह क्षेत्र पारिवारिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। जनपद कानपुर देहात का पुखरायां एक बड़ा बिजनेस हब है यहां पर आसपास के तमाम कस्बा और गांव के लोग व्यापार और खरीदारी करने के लिए आते हैं इस प्रोजेक्ट के लगने से स्थानीय लोगों को काफी मनोरंजन और हाईटेक सुविधा प्राप्त होगी.

पुलिस सेवाएं आम आदमी के और नजदीक पहुंचे: एसपी

» ग्राम प्रतापपुर बसौसी में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। थाना शिवली क्षेत्रांतर्गत ग्राम प्रतापपुर में नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र क उद्घाटन पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय कानपुर देहात द्वारा किया गया।अब पुलिस जनता के द्वार तक पहुंचेगी। पुलिस सहायत केंद्र पुलिस वजनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे। यह केंद्र भारत सेवा आश्रम की अध्यक्ष शुभा मिश्रा के सहयोग से स्थापित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सहायता केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को त्वरित पुलिस सहायता मिलेगी, छोटे विवादों का मौके पर समाधान होगा तथा महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इससे ग्रामीणों को थाने तक आने की असुविधा से राहत मिलेगी और अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने भारत सेवा आश्रम के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे केंद्र पुलिस और जनता के बीच विश्वास और समन्वय को और मजबूत करेंगे।उद्घाटन कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी मैथा, क्षेत्राधिकारी रसूलाबाद आलोक कुमार, थाना प्रभारी शिवली प्रवीन कुमार, भारत सेवा आश्रम के सदस्य, पुलिसकर्मी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

आशा व आशा संगिनियों का सड़कों पर फूटा गुस्सा

मुख्य सड़कों से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी, उप जिलाधिकारी को सौंपा मांगों का ज्ञापन

- तीन साल से अधिक समय से आशा व आशा संगिनियों का मानदेय लंबित
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में धरना, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई
- सड़कों पर उतरकर मुख्य मार्गों से कलेक्ट्रेट तक किया प्रदर्शन
- हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर की जोरदार नारेबाजी
- मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा
- प्रदर्शन का नेतृत्व अध्यक्ष मिथिलेश सोलंकी ने किया
- 'सिर्फ आश्वासन मिल रहे, समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं'—आरोप
- वेतन भुगतान की कोई समय-सीमा तय न होने से बढ़ा आक्रोश
- मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद।आशा एवं आशा संगिनियों की लंबित मांगों को लेकर जनपद में लगातार असंतोष बढ़ता जा रहा है। बुधवार को आशा बहू और आशा संगिनियां हाथों में बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरीं और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचीं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा।

इससे पहले आशा एवं आशा संगिनियों का धरना प्रदर्शन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में चलता रहा, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया। सुनवाई न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तेज कर दिया।

तीन वर्षों से वेतन लंबित होने का आरोप

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान कई बार पत्राचार हुआ और आश्वासन भी मिले, लेकिन अब तक मानदेय/सैलरी का भुगतान नहीं हो सका है। आशा एवं आशा संगिनियों को यह तक नहीं पता कि उनका वेतन कब उनके खातों में पहुंचेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं अध्यक्ष मिथिलेश सोलंकी ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए कोई अधिकारी ठोस कदम नहीं उठा रहा है।

फाइलों में कैद हैं समस्याएं

आशा एवं आशा संगिनियों का कहना है कि उनकी समस्याएं शासन और जिला प्रशासन की फाइलों में कैद होकर रह गई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस संबंध में पहल कौन और क्यों करेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब केवल आश्वासन देकर काम चलाया जा रहा है, तो उनकी समस्याओं को जानबूझकर दबाया जा रहा है।

व्यापार बंधु की बैठक में फतेहगढ़ मंगल बाज़ार पर प्रतिबंध लगाने की मांग

व्यापार बंधु की बैठक लेते मुख्य विकास अधिकारी

बैठक में उठे अन्य कई मुद्दे, आरटीओ कार्यालय की कार्य प्रणाली पर संदेह जताया

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फर्रुखाबाद द्य आरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली संदेह जनक होने पर व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में सवाल उठाया। व्यापारियों ने कहा कि कार्यालय के कर्मचारी आवेदन करने वाले व्यक्ति से सीएससी पर जाने की बात कहते हैं जिससे प्रतीत होता है कि कार्यालय में कार्य की पारदर्शिता नहीं है । जिला व्यापार बंधु समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ की अध्यक्षता में की गई । इस दौरान बैठक में व्यापारियों ने आरटीओ कार्यालय की कार्य प्रणाली संदेह जताते हुए कहा कि आरटीओ कर्मचारी आवेदक से सीएससी पर जाने को कहते हैं जो उचित व पारदर्शी नहीं है। इस पर सीडीओ ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। व्यापारियों ने रोड पर ई रिक्शा चालक तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर भी आपत्ति जताई तो सीडीओ ने क्षेत्राधिकारी पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं । व्यापारियों द्वारा फतेहगढ़ के मंगल बाजार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई द्य इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने विचार करने के लिए कहा है । व्यापारियों ने नगर में अतिक्रमण को हटाने, रेलवे रोड पर पुलिया व नाली का समतलीकरण एक लेवल पर कराने की मांग की द्य मुख्य विकास अधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद को मौके का निरीक्षण कर समस्या को दूर करने के निर्देश दिए ।

डिप्टी सीएम के सामने 'धक्का-तंत्र', मर्यादा तार-तार

शांति भोज में अशांति

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। जिस मंच पर शांति, संवेदना और अनुशासन होना चाहिए था, वहीं सत्ता का असंयम फूट पड़ा। गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी 'खब्बू' की माताजी के निधन पर आयोजित शांति भोज में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वही के एक वायरल वीडियो में साफ दिख रहा कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ही भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और नेता सच्चिदानंद पांडेय आपस में भिड़ गए। बात बहस से आगे बढ़ी और धक्का-मुक्की तक पहुंच गई मर्यादा की सारी सीमाएं तार-तार होती दिखी। स्वराज इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों नेता स्कूली बच्चों की तरह लड़ते दिखे—न कोई संयम, न कोई अनुशासन। सत्ता-संस्कार का दावा करने वाली पार्टी के मंच पर अनुशासन की शवयात्रा निकलती दिखी। स्थिति इतनी बिगड़ी कि उपमुख्यमंत्री के अंगरक्षकों को हस्तक्षेप करना पड़ा। सवाल उठता है जब उपमुख्यमंत्री के सामने यह हाल है, तो पर्दे के पीछे क्या तस्वीर होगी? विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। एक ओर संगठन 'डिसिप्लिन' की दुहाई देता है, दूसरी ओर वायरल क्लिप भाजपा की साख पर सीधी चोट कर रही है।

बता दें कि सच्चिदानंद पांडेय पूर्व में बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा में यह टकराव क्या पुराने राजनीतिक संस्कारों और नए सत्ता समीकरणों की टकराहट है? जहां श्रद्धांजलि और शांति का संदेश जाना था, वहां अशांति का तमाशा बन गया। संवेदना के क्षणों में सत्ता का अहंकार सबसे ऊंची आवाज बनकर उभरा। इस घटना से सवाल उठ रहा है कि क्या यह आंतरिक गुटबाजी अब सार्वजनिक अखाड़ा बन चुकी है? क्या संगठन अनुशासन सिर्फ पोस्टरों तक सीमित है? डिप्टी सीएम की मौजूदगी में भी अगर मर्यादा नहीं बची, तो जवाबदेही किसकी?

» अयोध्या में भाजपा की मर्यादा जमीन पर, नेता बने पहलवान, मंच बना अखाड़ा

किशनपुर कब्रिस्तान विवादः एडीए की 1000 वर्ग मीटर जमीन लापता, 100 साल पुराने दस्तावेजों की होगी जांच

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अलीगढ़। अलीगढ़ के किशनपुर क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) के रिकॉर्ड में जिस जमीन का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर दर्ज है, 28 जनवरी को मौके पर पैमाइश के दौरान वहां मात्र 1400 वर्ग मीटर जमीन ही उपलब्ध मिली है। करीब 1000 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन का हिसाब न मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया है। एडीए ने मौके पर अब अपनी वाउंड्री लगा दी है और स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया है।

एडीए अधिकारियों के अनुसार, यह जमीन लगभग 40 साल पहले अधिग्रहीत की गई थी। लंबे समय तक देखरेख के अभाव और निगरानी न होने के कारण भू-माफिया ने धीरे-धीरे इस पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में कब्रिस्तान के समीप मिली जमीन में भारी अंतर पाए जाने के बाद, एडीए ने अब आसपास की जमीनों का भी जीपीआर (ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार) सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस तकनीक के माध्यम से जमीन के नीचे के निर्माण और सीमाओं की सटीक स्थिति का पता लगाया जाएगा। प्राधिकरण अब केवल वर्तमान स्थिति पर ही संतोष नहीं कर रही है, बल्कि विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए 100 साल पुराने दस्तावेजों को खंगालने की तैयारी की जा रही है। एडीए के निशाने पर वे लोग हैं जिन्होंने कब्रिस्तान के आसपास की जमीनें खरीदी या बेची हैं।

सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आसपास की सभी संपत्तियों की पैमाइश नए सिरे से की जा रही है ताकि 1000 वर्ग मीटर जमीन का पता लगाया जा सके। इसके अलावा जिस जमीन को बुधवार को कब्जा मुक्त कराया है उसके संबंध में बताया गया था कि कब्रिस्तान है लेकिन मौके पर इस तरह का कोई प्रयोजन नहीं था। हम लोगों ने एक महीने पहले ग्राउंड पैनीट्रेटिंग रडार सर्वे कराया था जिससे जानकारी मिली कि नीचे कोई भी संरचना नहीं है।

51 मुकदमों वाला कुख्यात अपराधी करा रहा 'महापंचायत'

कानून को खुली चुनौती

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में कानून-व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात अपराधी दिलीप वर्मा उर्फ़ डीके उर्फ़ अविनाश चौधरी के समर्थन में कराई जा रही महापंचायत की खबर से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अपराधी भीड़ और धनबल के सहारे न्याय व्यवस्था पर दबाव बनाएंगे?

» महापंचायत की खबर से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप

70 लाख रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में दिलीप वर्मा (फ़ाइल फ़ोटो)

प्राप्त दस्तावेजों और आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार, दिलीप वर्मा के खिलाफ अयोध्या, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, गोंडा सहित कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 51 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, जबकि कई अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं।

सूत्रों के मुताबिक अपने खिलाफ दर्ज मामलों को कमजोर कराने और प्रशासन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से दिलीप वर्मा ने विभिन्न संगठनों को आगे कर यह महापंचायत आयोजित कराई है। बताया जा रहा है कि इसमें अपराध से अर्जित संपत्ति और धनबल का खुला इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, बीते दिनों थाना तारुन पर अनैतिक दबाव बनाने और पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की साजिश भी इसी नेटवर्क से जुड़ी बताई जा रही है।

प्रशासनिक सूत्र मानते हैं कि यह आयोजन केवल पंचायत नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए कानून और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। यूपी गैंगस्टर एक्ट में कई बार जेल जा चुका अपराधी अब खुलेआम भीड़ जुटाकर संदेश देना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन महापंचायत, अवैध धन और अपराधी नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करेगा? फिलहाल पूरा मामला जनपद में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

बिना अनुमति महापंचायत पर कार्रवाई, बैनर-होर्डिंग्स हटाए

जिला प्रशासन ने कुख्यात अपराधी दिलीप वर्मा की प्रस्तावित महापंचायत को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गांधी पार्क में किसी भी प्रकार की पंचायत या सभा की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद प्रचार किए जाने पर पुलिस ने देर रात शहर भर में लगे बैनर और होर्डिंग्स हटवा दिए। सूत्रों के मुताबिक, जनपद में पहले से ही धारा 144 लागू है, ऐसे में भीड़ जुटाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने आयोजकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से जुड़े व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक मंच के जरिए दबाव बनाने की कोशिश को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है और गांधी पार्क समेत आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

भदरसा रेप कांड: डीएनए रिपोर्ट बदल दी गई, हमें खतरा है

» सपा नेता बरी, नौकर राजू को 20 साल की सजा 50 हजार जुर्माना

» विशेष लोक अभियोजक ने कहा फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

पीड़िता की मां

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। मुझे लगता है डीएनए रिपोर्ट बदलवा दी गई है, अब हमें खतरा है÷ यह दर्द और डर भरी आवाज़ है उस मां की, जिसकी 12 वर्षीय बेटी के साथ 29 जुलाई 2024 को भदरसा इलाके में गैंगरेप हुआ था। इसी मांग और आशंका को लेकर पीड़ित परिवार अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।

पाक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने चर्चित मामले में सपा नेता मोईद खान को बरी कर दिया, जबकि उसके नौकर राजू खान को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। अदालत ने फैसले का आधार डीएनए रिपोर्ट को बनाया। यहीं से पीड़ित परिवार की पीड़ा और अविश्वास शुरू होता है। पीड़िता की मां का आरोप है कि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, ठीक से पैरवी नहीं हो पाई, पुलिस जांच में गंभीर खामियां रहीं और इसी वजह से मुख्य आरोपी छूट गया। उन्होंने कहा कि जब आरोपी जेल में थे, तब भी डर था, अब बरी होने की खबर से खतरा और बढ़ गया है। परिवार ने सुरक्षा की मांग भी उठाई है। बता दें कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 13 गवाह पेश किए, लेकिन कथित वीडियो सबूत पेश नहीं हो सका। पुलिस जांच में घटनास्थल को लेकर विरोधाभास भी सामने आए। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की है।

स्वराज इंडिया FOLLOW UP

अयोध्या का देसी स्वाद: प्रदीप बाटी वाले' की अनकही कहानी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी की गलियों में जहां आस्था, इतिहास और परंपरा की खुशबू बसी है, वहीं स्वाद की दुनिया में भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो दिल तक उतर जाती हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास स्थित 'प्रदीप बाटी वाले' की छोटी-सी दुकान ऐसी ही एक पहचान है, जहां पहुंचते ही इंसान को पूर्वांचल के देसी स्वाद की याद आ जाती है।

करीब 33 साल पुरानी इस दुकान की शुरुआत बेहद सादगी से हुई थी। दुकान के मालिक खुद पूर्वांचल से हैं और वहीँ की मिट्टी में पली-बढ़ी रेसिपी आज भी उनके हाथों में जिंदा है। न कोई तामझाम, न कोई चमक-दमक–बस मेहनत, ईमानदारी और स्वाद से भरा हुनर। यहां बनने वाली बाटी आज भी पुराने देसी तरीके से तैयार की जाती है। पहले आटे को सहेजकर गूंथा जाता है, फिर बाटियों को शुद्ध तेल में सेंका जाता है और ऊपर से डाली जाती है देसी घी की खुशबूदार परत। साथ में मिलता है बेगन-आलू का चोखा, कटा प्याज और तीखी-मीठी चटनी।

सबसे खास बात यह है कि सिर्फ 40 रुपए में पूरी थाली मिल जाती है, जिसमें स्वाद भी भरपूर और संतोष भी पूरा। यहां बैठकर जब गरम-गरम बाटी को घी में डुबोकर खाया जाता है, तो लगता है जैसे किसी गांव के आंगन में बैठकर मां के हाथ का खाना खा रहे हों। मिट्टी की सौंधी खुशबू, घी की महक और चोखे का देसी तड़का सब मिलकर दिल को छू लेते हैं। आज जब फास्ट फूड और दिखावे का दौर है, ऐसे में 'प्रदीप बाटी वाले' जैसी दुकानें संस्कृति और स्वाद की विरासत बन चुकी हैं। जो लोग असली पूर्वांचली बाटी-चोखा का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह अयोध्या की एक छुपी हुई लेकिन अनमोल पहचान है।

पेट्रोल भरवाते ही बाइक बनी आग का गोला

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में नहर बाग पेट्रोल टंकी के सामने राम पथ पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। पेट्रोल भरवाने के तुरंत बाद जैसे ही चालक ने स्टार्ट किया, बाइक धू–धू कर जल उठी। चालक ने फुर्ती दिखाते हुए बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते मोटरसाइकिल आग का गोला बन गई और पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा–तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे।

रायबरेली में गांधी परिवार पर याचिका

अदालत ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

सरकारी जमीन व तालाब पर कथित कब्जे का आरोप, सोनिया-प्रियंका-राहुल समेत 45 नामजद

स्वराज इंडिया न्यूज

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार के सदस्यों के खिलाफ अदालत में दायर एक याचिका ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इस याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कुल 45 लोगों को नामजद किया गया है।

मामला सरकारी भूमि और तालाब की जमीन पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए निर्माण से जुड़ा हुआ है। एपीएमएल कोर्ट ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए इसे संज्ञान में लिया है और शहर कोतवाली पुलिस को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तिथि तय की है। पाजा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र शरण श्रीवास्तव और वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष लाखन सिंह की ओर से दाखिल याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

याचिका में कुल 45 लोगों को पक्षकार बनाया गया है, जिनमें सोनिया गांधी (सांसद), राहुल गांधी (सांसद), प्रियंका गांधी वाड्रा (कांग्रेस महासचिव), रायबरेली के तत्कालीन/वर्तमान जिलाधिकारी, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, निर्माण और मान्यता से जुड़े अन्य संबंधित व्यक्ति शामिल हैं।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि पूरे मामले में सभी नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए।

➪ **वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े दो मामलों की सुनवाई अब 19 फरवरी को**

याचिका के प्रमुख बिंदु

- सरकारी भूमि और सार्वजनिक तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप
- कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भवन निर्माण कराया गया
- निर्माण के बाद उक्त परिसर को सीबीएसई से मान्यता दिलाने का दावा
- आरोप है कि इस पूरे मामले में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध रही
- याचिका में दावा किया गया है कि गांधी परिवार के सदस्यों ने भी इस प्रक्रिया में सहयोग किया

किन-किन को बनाया गया पक्षकार

याचिका में कुल 45 लोगों को पक्षकार बनाया गया है, जिनमें सोनिया गांधी (सांसद), राहुल गांधी (सांसद), प्रियंका गांधी वाड्रा (कांग्रेस महासचिव), रायबरेली के तत्कालीन/वर्तमान जिलाधिकारी, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, निर्माण और मान्यता से जुड़े अन्य संबंधित व्यक्ति शामिल हैं।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि पूरे मामले में सभी नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए।

एपीएमएल कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तलब की है। साथ ही शहर कोतवाली पुलिस को तथ्यों की पड़ताल कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। रिपोर्ट सुनवाई की 9 फरवरी को होगी।

वाराणसी में राहुल गांधी से जुड़े दो मामलों की सुनवाई टली

इस बीच वाराणसी में भी राहुल गांधी से जुड़े दो अन्य मामलों की सुनवाई टल गई है। ये मामले विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में विचाराधीन हैं। अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान व ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम को लेकर कथित टिप्पणी को लेकर याचिका दखिल की गई है। दोनों मामलों में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी । अब अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए 13 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

गोरखपुर। पूर्वांचल और पूर्वोत्तर भारत को सीधा सड़क संपर्क देने वाले गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया अब ज़मीनी स्तर पर तेज हो गई है। परियोजना के एलाइनमेंट में आने वाली भूमि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए 13 राजस्व गांवों की चयनित गाटों की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक गोरखपुर तहसील सदर क्षेत्र में लागू की गई है, जहां कुल 69.57 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

इस संबंध में विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी (एसएलओ) हिमांशु वर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निर्देश पर उप निबंधक प्रथम एवं द्वितीय, तहसील सदर को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित गाटों का क्रय-विक्रय, बैनामा या रजिस्ट्री नहीं की जाएगी।

क्यों लगाई गई रजिस्ट्री पर रोक: प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे एलाइनमेंट में आने वाली भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक इसलिए लगाई गई है ताकि अधिग्रहण के दौरान भू-माफियाओं की सक्रियता रोकी जा सके। भूमि के स्वामित्व में कृत्रिम बदलाव न हो। किसानों और वास्तविक भू-स्वामियों को मुआवजे से वंचित न होना पड़े। ताकि परियोजना में कानूनी अड़चनें उत्पन्न न हों। अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में कई बड़ी परियोजनाओं में भूमि की रजिस्ट्री जारी रहने के कारण विवाद और देरी की स्थिति बनी थी, जिससे सीख लेते हुए यह कदम पहले ही उठा लिया गया है।

69.57 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना की तैयारी, किसानों को तय नियमों के तहत मिलेगा मुआवजा

कहां से कहां तक बनेगा एक्सप्रेसवे

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की शुरुआत जगदीशपुर जंगल कौड़िया बाईपास स्थित करमहा क्षेत्र से प्रस्तावित है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले से निकलकर कुशीनगर की हाटा, कसया और तमकुहीराज तहसीलों से गुजरेगा। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) तक पहुंचेगा। यह परियोजना पूर्वांचल को उत्तर-पूर्व भारत से जोड़ने वाली एक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद अहम सड़क परियोजना मानी जा रही है।

इन 13 गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित

अधिग्रहण के दायरे में आने वाले गांवों में करमहा तप्पा पतरा, महराजी तप्पा पतरा, सोनवे गोनाराहा, अगया तप्पा पतरा, मटिहनिया सुमाली, उस्का, नैयापार खुर्द, भरपुरवा, महुअवा खुर्द, राउतपार तप्पा केवटली, हेमछापर, लुहसी शामिल हैं। इन गांवों में अलग-अलग रकबे की कृषि और अन्य श्रेणी की भूमि अधिग्रहण के तहत ली जाएगी।

किसानों को कैसे मिलेगा मुआवजा

विशेष भूमि अध्यापि अधिकारी हिमांशु वर्मा ने स्पष्ट किया है कि भूमि अर्जन की पूरी प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत की जाएगी। इसके अंतर्गत बाजार दर के अनुसार मुआवजा, ग्रामीण क्षेत्र में गुणक (मल्टीप्लायर) का लाभ, स्थायी परिसंपत्तियों (पेड़, कुआं, भवन आदि) का अलग मूल्यांकन व आपत्तियों के निस्तारण का अवसर दिया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अगले चरण में प्रभावित गाटों की अधिसूचना जारी की जाएगी। भूमि का संयुक्त सर्वे और मापन होगा। किसानों से आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद अंतिम अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी

अविमुक्तेश्वरानंद का योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

वाराणसी। ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगदुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि अब समय प्रमाण मांगने का नहीं, बल्कि प्रमाण देने का है। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण सनातनी समाज की ओर से वे मुख्यमंत्री से उनके 'हिन्दू' होने का साक्ष्य मांगते हैं, जिसकी कसौटी गो-सेवा और धर्म-रक्षा है।

शुक्रवार को काशी स्थित शंकराचार्य घाट के श्रीविद्यामठ में पत्रकारों से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि यदि 40 दिनों के भीतर गोमाता को उत्तर प्रदेश में 'राज्यमाता' का दर्जा नहीं दिया गया और मांस निर्यात पर सख्त निर्णय नहीं लिया गया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि 10-11 मार्च को लखनऊ में संत समाज की धर्मसभा बुलाई जाएगी, जहां मुख्यमंत्री को 'नकली हिन्दू' घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है। शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू होना केवल भाषणों या भगवा पहनने तक सीमित नहीं है। जो सरकार गोवंश की रक्षा नहीं कर सकती, उसे हिंदू कहलाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मांस निर्यात पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के कुल मांस निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है और 'भैंस के मांस' के नाम पर गोवंश के वध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि गो-रक्षा की मांग उठाने वालों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उनकी छवि धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शंकराचार्य ने महाराष्ट्र द्वारा देशी गाय को 'राज्यमाता' और नेपाल में गाय को 'राष्ट्रीय पशु' का दर्जा दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि भगवान राम और कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश में भी गोमाता को वही सम्मान मिलना चाहिए।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86769 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com